

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Chairman, Sir, as you know, like, in the recent past, there was MV Ganga Vilas, the cruise, which, ultimately created history. The MV Ganga Vilas, that is, river cruise, started its voyage from Banaras to Dibrugarh, crossing more than 27 river systems and 3,200 kilometers. So, this created a history because, earlier, this had never happened. The people had an apprehension. They thought that गंगा में पानी नहीं है, जहाज फंस जाएगा; ब्रह्मपुत्र में पानी नहीं है, यह कूज नहीं चल सकता है, लोगों ने ऐसी टिप्पणी भी की और आलोचना भी की। आखिर में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि हमें ऐसा माहौल खड़ा करना होगा कि हमारी नदी में जो शक्ति है और हमारी नदी के दोनों पार जो हमारी सांस्कृतिक धारा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के जो मूल्य हैं, भारत की इन चीजों को दुनिया देखे। उसी हिसाब से जब इन चीजों को ध्यानपूर्वक लिया गया है, ultimately River Cruise MV Ganga Vilas ने ऐसा माहौल खड़ा किया, अब देश के अंदर एक के बदले नौ कूज चलने लगे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

1.00 P.M.

†DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

MR. CHAIRMAN: Further discussion on the Working of the Ministry of New and Renewable Energy. On 5th August, 2024, Shri Amar Pal Maurya had not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Shri Amar Pal Maurya to continue his speech. Shri Amar Pal Maurya.

† Discussion continued from 5th August, 2024.

श्री अमर पाल मौर्य (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, कल सदन का समय पूरा होने के पहले मुझे कुछ समय मिला था, इसके लिए मैं माननीय उपसभापति जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आज पुनः समय मिला, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, मैं कल कह रहा था कि जब से सरकार बनी है माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत छोटे-छोटे कदमों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। उसी दृष्टि में वे छोटे कदम बहुत बड़े नतीजे देते हैं। मोदी जी ने एक छोटा आंदोलन एलईडी बल्ब के लिए चलाया था और वह आंदोलन इतना परिणामकारी सिद्ध हुआ, उसका परिणाम यह निकला कि जब करोड़ों परिवारों को एलईडी बल्ब देने की योजना चली, उस एलईडी बल्ब के माध्यम से 45 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हुई। यह है नरेन्द्र मोदी सरकार की दृष्टि। उन्होंने छोटे विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया।

महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा विकास भी और पर्यावरण भी, उन्होंने दोनों को साथ में जोड़ने का काम किया। उन्होंने एक अभियान लिया - 'एक पेड़ माँ के नाम', जिसमें पूरा देश आज सहभागी बना हुआ है। उस सहभागिता का यह परिणाम है कि पर्यावरण की संरचना की जो उनकी कल्पना है, आने वाले समय में बड़े रूप में इसकी सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया स्रोत डेवलप होगा। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की पर्यावरण के प्रति, ग्रीन एनर्जी के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। महोदय, प्रकृति का संकट किसी एक देश का संकट नहीं है, अपितु यह पूरे विश्व का संकट है। हमारी तो धारणा हजारों साल पहले से वसुधैव कुटुंबकम की रही है कि विश्व एक परिवार है। हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान दिया है। महोदय, जब भारत को आजादी प्राप्त हुई, तो आजादी के प्राप्त होने के बाद देश को प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता थी, जिस तरफ सरकारों का ध्यान जाना चाहिए था, भारत को भारत के नजरिये से सोचने की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय की सरकारों ने भारत को अमेरिका और इंग्लैंड बनाने का सपना दिखाया, जबकि भारत सुदूर गाँव के क्षेत्र में बसता था। उस गाँव में रहने वाला जो किसान था, उस गाँव में रहने वाला जो मजदूर था, जो नौजवान था, देश की आजादी के बाद से ही उस दिशा में सोचने की आवश्यकता थी। महोदय, हमारे यहाँ तो प्रकृति ने हमको जीवन में सब कुछ सिखाया है। उस समय की सरकारों ने प्रकृति से ही ज्ञान ले लिया होता, तो अच्छा होता। जल देवता थे, उनसे बिजली की चिंता करते; पवन देवता थे, पवन चक्की की चिंता करते; और तो और सूर्य देवता थे, उनसे ही कुछ शिक्षा ग्रहण कर लिए होते, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में गाँव का गरीब नहीं था, गाँव का किसान नहीं था, गाँव का नौजवान नहीं था।

देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था, तो उसके बनने के बाद जब उद्घाटन का दिन आया, तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 'पीएम सूर्य घर योजना' को लांच किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में किसान भी था, गरीब भी था और नौजवान भी था। महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने इसका एक

लक्ष्य रखा। उन्होंने पीएम किसान सौर बिजली के माध्यम से एक करोड़ परिवार के लोगों को इस योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य बनाया। आज इसमें लगभग 1 करोड़, 28 लाख से अधिक का पंजीकरण हो गया है, लगभग 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए हैं।

महोदय, सूर्य भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, शिक्षा देते हैं, यह उनसे ग्रहण करने की आवश्यकता थी। हमारे यहां तो कहते हैं कि बजरंग बली जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने गए थे। उनके जीवन से ही कुछ प्रेरणा ले लिए होते। हनुमान जी जब सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तो उनको आठ सिद्धियां और नौ निधियां प्राप्त हुईं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके विषय में कहा - "अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।" यह उनका ज्ञान था, उनसे कुछ ज्ञान लिए होते। महोदय, उस ज्ञान का इतना अच्छा परिणाम हुआ कि जब वे लंका में गए, भगवान राम ने उनको भेजा, तो वे माता सीता का पता लगाने के लिए गए। उन्होंने माता सीता का पता तो लगाया, लेकिन उनके ज्ञान की दृष्टि देखिए कि उन्होंने स्वयं ही टेक ऑफ किया और स्वयं ही लैंडिंग की। उन्होंने लंका में जो किया कि - तेल रावण का, कपड़ा रावण का, लंका रावण की और जो सोने की लंका जली भी, वह भी रावण की थी। अगर ये इनसे भी शिक्षा लिए होते, तो साथियो, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का - देश की आजादी के बाद, इनके कार्यकाल में बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, जो समस्याएँ दी गई थीं, वे पहले ही समाप्त हो गई होतीं। लेकिन, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, चूँकि वे एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए उनके केंद्र बिंदु में गरीब था। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद एक सब्जी बेचने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में सब्जियाँ उगाई हैं। इतना ही नहीं, हमारे घर में जब ट्यूबवैल नहीं होता था, तो हम रहट चलाकर भी खेतों की सिंचाई करते थे। हमारे पास रात में पढ़ने के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो हम मिट्टी के तेल का दीपक जलाकर, उसकी रोशनी में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, आज मेरी आंखों में जो चश्मा लगा है, उसके लिए अगर कोई दोषी है, तो ऐसा इस देश की आजादी के बाद सत्ता पर राज करने वाले ऐसे परिवार के लोगों के कारण है।

महोदय, इतना ही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जब पीएम सूर्य घर की योजना को लॉन्च किया, तो आज पीएम सूर्य घर योजना इतनी व्यापक होगी कि पीएम सौर ऊर्जा का उदय और भारत का उदय - यह दोनों एक साथ हो करके रहेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। महोदय, चाहे वह कोई भी, चाहे वह राहु हो या केतु हो, चाहे जितने भी ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे ...**(समय की घंटी)...**

श्री उपसभापति: मौर्य जी, यह आपकी मैडेन स्पीच है, परन्तु और 2 मिनट में खत्म कीजिए।

श्री अमर पाल मौर्य: महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करना चाहूंगा।

महोदय, मोदी जी ने जो लक्ष्य तय किया है, जो मोदी जी का लक्ष्य है - हरित भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत। मोदी जी ने इस 'विकसित भारत' की

परिकल्पना जो तय की थी, तो उन्होंने कहा था कि यह लक्ष्य देश के सारे नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं को, बहनों को अपने जीवन में तय करना है। वह लक्ष्य आने वाले समय में कैसा होगा, कि:

*"पूर्ण प्रखरतम उज्ज्वल रवि सम,
विकसित राष्ट्र साकार प्रकट हो,
सुखी, सबल समरस भारत हो,
एक दिशा में हो प्रयासरत,
राष्ट्र समूचा चले विजयपथ,
जग में गुंजे जय-जय भारता,
जग में गुंजे जय-जय भारता।"*

बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, India made five commitments at COP26 which include net zero emissions by 2070, non-fossil energy capacity to 500 Gigawatts by 2030, carbon intensity down to 45 percent by 2030, fulfilment of 50 percent of India's energy requirements through renewable resources by 2030, and reduction of 1 billion tonnes of carbon emissions from the total projected emissions. But India still remains significantly behind its COP26 goals. As of May, 2024, India could achieve merely 38 percent of the 2030 targets. Climate change and its effects are becoming increasingly apparent, highlighting the urgency of transitioning to renewable energy. The budget of the Ministry has been raised to Rs.19,100 crores, which is an 87 percent boost and correctly so. But the issue is implementation. Maharashtra, for instance, the highest consumer in the country, consumed 126 terawatt hours in 2021. This has been projected to reach 200 terawatt by 2028. And, in 2023, renewable energy contributed to just 17 percent to the total energy generation of the State and 34 percent to its installed capacity. Despite Maharashtra's potential to generate about 2 lakh megawatts of renewable energy, 11.79 percent of India's total, its installed capacity as on 30th June, 2024, was only around 17,000 megawatts. Similarly, the PM-KUSUM Scheme intended to promote solar power projects in the farmlands has underperformed significantly with gross under-utilisation of funds and minimal progress towards set targets. The Budget places a strong emphasis on solar power by allocating approximately 85 percent of the total Budget to the sector with 44 percent dedicated

specifically to off-grid solar power. Once again, implementation is the question. An example which could be cited here is, although 4 lakh solar pumps have been sanctioned for off-grid areas in Maharashtra, only 79,000 have been installed.

सर, अगर 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की बात की जाए, तो मैं इसके बारे में कहूँगी कि यह निश्चित रूप से लाभदायी हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में देहातों की जनता irregular electricity supply से त्रस्त है, इसलिए निश्चित रूप से यह योजना उनके लिए लाभदाई होगी। जहां तक इस योजना का नाम है, इस योजना के नाम से मुझे एक बात ध्यान में आती है। सर, चूहा पिंजरे में क्यों फँसता है? चूहा पिंजरे में इसलिए फँसता है कि पिंजरे में उसे समझ में नहीं आता है कि पिंजरे में रखी रोटी उसे मुफ्त में क्यों मिल रही है। सर, यहाँ जहाँ तक नाम का संबंध है, तो नाम में सिर्फ शब्द 'मुफ्त' है, लेकिन योजना में कुछ भी मुफ्त नहीं है। यह योजना सब्सिडाइज़्ड योजना है। इसका अर्थ यह है कि किसान को बैंक जाना होगा, कर्ज के लिए एप्लीकेशन देना होगा, उसकी सब्सिडी सैंक्शन होती है, तभी उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। प्रश्न यह है कि आज किसान को बैंक्स में जाकर लोन लेना बहुत कठिन हो गया है। क्यों कठिन हो गया है? कठिन इसलिए हो गया है, क्योंकि जब कर्ज माफी दी गई थी, तब प्रशासन के माध्यम से जो अपडेशन होना चाहिए था, उसमें बहुत विलंब हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का जो सिबिल स्कोर था, वह टोटली खराब हो गया है। इसके कारण आज किसानों के सिबिल स्कोर पर इतना भयानक प्रभाव पड़ा है कि कोई भी बैंक उन्हें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह विनती करती हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें, बैंकों को ताकीद करें। अगर ऐसा नहीं होगा, तो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा और यह योजना भी कागज पर ही रह जाएगी।

†سر، اگر پی ایم سوریه گھر مفت بجلی یوجنا کی بات کی جائے تو میں اس کے بارے میں کہوں گی کہ یہ یقینی طور پر فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیوں کہ آج ہمارے دیش میں دیہاتوں کی جنتا اریگولر الیکٹریسیٹی سپلائی سے ترست ہے۔ اس لیے یقینی طور پر یہ یوجنا ان کے لیے مفید ہوگی۔ جہاں تک اس یوجنا کا نام ہے، اس یوجنا کے نام سے مجھے ایک بات دھیان میں آتی ہے۔ سر، چوہا پنجرے میں کیوں پھنستا ہے؟ چوہا پنجرے میں رکھی روٹی اسے مفت میں کیوں مل رہی ہے۔ سر یہاں جہاں تک نام کا تعلق ہے، تو نام میں صرف شید مفت ہے۔ لیکن یوجنا میں کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ یہ یوجنا سبسڈائز یوجنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان کو بینک جانا ہوگا، قرض کے لیے ایپلیکیشن دینا ہوگا، اس کی سبسڈی سینکشن ہوتی ہے، تبھی اسے اس یوجنا کا لابیہ مل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کسان کو بینک میں جاکر لون لینا بہت مشکل ہوگیا ہے۔ کیوں مشکل ہوگیا ہے؟ مشکل اس لیے ہوگیا ہے، کیوں کہ جب قرض معافی دی گئی تھی، تب پرشاسن کے مادھیم سے جو ایڈیشن ہونا چاہیئے تھا، اس میں بہت ولیمب ہوا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کا جو سول اسکور تھا، وہ ٹوٹلی خراب ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج کسانوں کے سول اسکور پر اتنا اثر پڑا ہے کہ کوئی بھی بینک انہیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔

سر، میں آپ کے توسط سے منتری مہودے سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں، بینکوں کو تاکید کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کسان اس یوجنا کا لابیہ نہیں اٹھا پائے گا اور یہ یوجنا بھی کاغذ پر ہی رہ جائے گی۔

† Transliteration in Urdu script.

I would like to speak additionally about the DISCOM Center, which faces significant losses in many States. It could be integrated into the PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana through the RESCO model. Sir, this would involve...(*Time-bell rings.*) All right, Sir, thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please complete the sentence.

DR. FAUZIA KHAN: This would involve leasing rooftops and installing systems, relieving consumers of upfront costs, and aiding discoms in meeting renewable energy targets. Let us move towards a secure future for our upcoming generations in real earnest. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, on behalf of the AIADMK Party, and also my leader, Shri Edappadi K. Palaniswami, I rise to participate in the Discussion on the Working of the Ministry of New and Renewable Energy. The Central Government, in the Union Budget 2024, has allocated Rs.19,100 crores to the Ministry of New and Renewable Energy. The Ministry deals with areas like solar power, hydro power, National Green Energy Mission, apart from the nuclear power. I would like to raise some important issues for the consideration of the Government.

Tamil Nadu has a long coastline in the country. It is 1,076 kilometer long and it is the second largest coastline in the country after Gujarat. The coastline of Tamil Nadu is best suited for producing maximum wind energy. May I know whether the Government has set any target for generating wind energy and enhancing the wind energy capacity so that the dependence on the conventional forms of energy comes down? During the period of former Chief Ministers, Dr. Amma Jayalalitha and Shri Edappadi K. Palaniswami, they had sanctioned more plants to produce more wind energy. Will the Government of India consider setting up wind energy plants along the Tamil Nadu coastline?

Regarding hydro power, there is a need to retain the rainwater during the monsoon, which India gets copiously. Interlinking of rivers may help retain and restore water. That is what our leader, Shri Edappadi K. Palaniswami, has requested. Godavari, Palar and Cauvery have to be connected. Still, this work is pending. The South Pennaru

River flows from Karnataka State and comes to Tamil Nadu. We have also requested many times that we need to construct one dam at Anekal, Podur, Venniyode, which is a place in Krishnagiri district. If that dam is constructed, we can produce hydroelectric power and also take care of the water problems of the dry area, especially the villages of Krishnagiri district, like Vepanapalli, Maharajakadai, Mekalachinnampalli, Vardanapalli, Bargur and Mattoor, where we can do these kinds of things.

Regarding solar energy, in this Budget, and the earlier Budget also, the Government has called for installing solar panels in each home. Many Members raised this issue. But, for that, incentives must be given to establish this kind of solar panels on the roof of the house. There is an impression that incentives given do not commensurate with the targets of production of solar energy. The Government has to consider giving more incentives. Our former Chief Ministers, Amma and Edappadi K. Palaniswami, took a lot of efforts to install solar panels in the southern parts of the country, like Tuticorin. I request the Central Government to encourage setting up good quality solar panels on the roofs of the Government institutions at the subsidised rate. The Government should come forward to give more incentives, more subsidies on maintenance of panels.

Now, coming to the nuclear energy, I would like to state that the nuclear energy is being produced throughout the world and it is necessary for India also. But, here, I would like to raise a very important issue. In India, some States are not coming forward to establish that nuclear energy plants. In Tamil Nadu, Kudankulam is one of the big plants established. But the people are having the fear that the wastage will affect the area. At the same time, neighbouring States like Kerala are not interested to have that kind of plant. Sir, whatever electricity is produced from the nuclear energy plants at Kudankulam and other places is shared with other States also. My request to the Government is not to share electricity with States, which are not interested and which do not allow establishment of such nuclear energy plants. This is my request.

Sir, as the time is limited, I would conclude by making a mention about the rooftop panel. You have to give it to reputed companies. It is not about only giving subsidy and establishing the solar panels to produce the solar energy, but, at the same time, we have also to see that the companies must maintain and help the people because maintenance part will be very difficult for the poor people. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Darshana Singh.

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने और पूरे देशवासियों की तरफ से लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर बधाई देती हूँ।

महोदय, आज भारत माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। हम रूस के बाद दूसरे देश हैं, जिसके पास Prototype Fast Breeder Reactor, (PFBR) की क्षमता है। PFBR भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर है। इस दूरदर्शिता के लिए मैं पूरे देश की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश ने 60 के दशक में PFBR की technique खोज ली थी और इसकी खोज महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जी ने की थी, लेकिन देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया और यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 6 दशक के लम्बे इंतज़ार के बाद देश में वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी, तो अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता मिली। पिछले एक दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। महोदय, आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोग करने वाला देश है। मानव समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में ऊर्जा एक इंजन का काम करती है। आज भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ी है, जो सीमित जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने वैकल्पिक उपाय ढूंढे हैं। वर्ष 2014 के बाद से भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वजह से आज भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में चौथे नम्बर पर आ गया है तथा देश में सौर, पवन और जैव ऊर्जा सहित अलग-अलग स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादकों में एक है और भारत इसका एक तरह से नेतृत्व भी कर रहा है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में सोलर रूफटॉप, सोलर पार्क और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज कई निजी कंपनीज़ सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। भारत में पवन ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2030 तक बिजली की 50 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने के लिए 500 गीगा वॉट गैर जीवाश्म ईंधन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, आज देश पवन टरबाइन और अन्य संबंधित उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। सर, आज माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न

प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है।

महोदय, WHO के अनुसार देश में लगभग 99 प्रतिशत लोग जिस हवा में सांस लेते हैं, वह वायु गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है तथा विश्व में प्रतिवर्ष 13 मिलियन से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। वह जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन व मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। विश्व की लगभग 80 प्रतिशत आबादी उन देशों में है, जो जीवाश्म ईंधन के शुद्ध आयातक हैं। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और भारत स्वयं के इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का 85 प्रतिशत और अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 54 प्रतिशत आयात करता है। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था जीवाश्म की कीमतों के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती रहती है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है।

महोदय, जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमतें लगातार बढ़ने और विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा होने के परिणामस्वरूप अब अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पेश बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केन्द्रीय बजट 2024-25 में ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक बताया। यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी और जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प के रास्ते में जीवन की हर छोटी-बड़ी चीजों के विकास के लिए चिंता की है, वह अपने आप में बहुत अहम है। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, उससे पहले मुझे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं-

"अवसर तेरे लिए खड़ा है,
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है,
तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है,
पल-पल है अनमोल
अरे भारत उठ आंखें खोला।"

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, proper functioning of the Ministry of New and Renewable Energy has become all the more relevant and important today. In fact, we are temporary residents on this earth. So, we have to pass on the same to the future generations. This is the concept which we all have to understand. We all were shocked and saddened on knowing the tragedy that befallen on the people of Wayanad. I was there for four days. Some of my colleagues also joined. Why I am stating all this here is,

our concept on development must be reshaped and revisited. So, for that, we need new and renewable energy. And we have to slowly shift from conventional energy. This is the reason why new and renewable energy sector becomes important. But, unfortunately, there is a contradiction in Government's approach. We are talking about promotion of new and renewable energy. At the same time, we are promoting conventional energy. Share of coal in our power basket is already 50 per cent. We are now adding capacity to our coal plants. Recently, 13.9 gw coal-fired power plant capacity was installed. What does it mean? It means that we are promoting coal. Sometimes, I doubt whether Adani Group is dictating the power policy of our Government. A top official of the Adani Group recently stated that India will continue to import coal in the coming years. How can they state it? The point, which I would like to make, is this. Can we promote coal import like this? When are we going to stop this? In addition to this, we are starting new coal plants in our country. At the same time, we are talking about new and renewable energy. This contradictory approach must be revisited. Sir, through you, I request the Ministry to seriously introspect about this.

There is a Report of the Standing Committee on Energy which was published in 2022. It talks about the rooftop solar programme. We had aimed to achieve 40 gw. of solar capacity by the end of 2022. But we could achieve only 10.4 gw. by the end of the year 2022. This was revealed by the Ministry in 2023. Why is this happening? According to the Standing Committee Report, there are three reasons. One is lack of information. Second is that it is a time-consuming process. And third is that there is delay in subsidies. I take this opportunity to request the Minister concerned to seriously introspect about these aspects. We have to promote rooftop solar programme in a bigger way.

Sir, there is no need to explain erratic rains and climate change further. What would be the impact of climate change on renewable power sector? It must be examined and studied properly by the Department because nothing is predictable. As I said just now, erratic rains, climate change and deforestation are increasing and nothing is predictable. This will surely affect the solar and renewable energy sector. How are we going to tackle this issue in the coming future? This should also be taken into consideration.

Sir, I would like to take this opportunity to make two demands. In Kerala, we have hundreds of houseboats. That is one of the main attractions of Kerala tourism. The Government can propose a project whereby these houseboats can have solar panels.

(*Time-bell rings.*) They use diesel generators. Instead of diesel generators, if they can propose a plan and fund it properly, then these can be replaced with solar panels. That will benefit Kerala tourism.

Finally, all our local body offices throughout the country must be transformed through solar panel system. That will create a model which will boost new and renewable energy sector in our country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Birendra Prasad Baishya. He is not there. Shri Mithlesh Kumar.

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने हमें नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट हमारे सम्माननीय नेता के विकसित भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इन नवप्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके, इस बजट का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के भीतर पर्याप्त अवसर पैदा करना है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाया गया बजट 2024-25 देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। यह बजट गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है, जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढाँचे और युवाओं के लिए रोजगार को प्रोत्साहित करेगा। मानव्यर, मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी, दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली एनडीए सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। मंत्रालय की नागरिक उन्मुख पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। मैं किसानों के लाभ के लिए चलाई गई 'पीएम कुसुम योजना' की शुरुआत करने के लिए बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं की अच्छी प्रगति देखी जा रही है।

उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो 'पीएम सूर्य घर बिजली योजना' प्रारंभ की गई है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करनी है। घरों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके द्वारा मुफ्त के साथ-साथ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक किलोवाट से लेकर पाँच किलोवाट तक के संयंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। एक किलोवाट के संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस प्रकार एक किलोवाट पर कुल 45,000 रुपये का अनुदान और दो किलोवाट पर केंद्र सरकार द्वारा 60,000 रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये, अर्थात् कुल

90,000 रुपये की छूट दी जा रही है। तीन किलोवाट से लेकर पाँच किलोवाट के संयंत्र की स्थापना पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 30,000 रुपये तक का अनुदान देकर, कुल 1,08,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... प्लांट की अनुमानित लागत 60,000 रुपये प्रति किलोवाट रहेगी एवं सोलर पैनल की कार्य क्षमता अवधि लगभग 25 वर्ष तक रहेगी। सोलर प्लांट स्थापना के उपरांत की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी। इसके साथ ही, इस संयंत्र की स्थापना के लिए सब्सिडी के बाद वाली धनराशि हेतु, बैंक में आसान किश्तों पर लोन की व्यवस्था भी की जा रही है। तीन किलोवाट का सोलर प्लांट मात्र 1,800 रुपये की ईएमआई पर लगाया जा सकता है, जिसके लिए मात्र सात प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक लोन मिलेगा। इस योजना से अधिक लाभ, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम पैदा होंगे।

मान्यवर, मैंने आपको यह इसलिए बताया है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे, तब बिजली के दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि तब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मिट्टी के तेल की छोटी-छोटी डिब्बी लेकर पढ़ा करते थे। महोदय, इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि मेरे जनपद शाहजहाँपुर में तीन प्लांट्स, दो 50-50 मेगावाट के और एक दस मेगावाट का कार्यरत है, जिसमें 110 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो बिजली घरों के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध हो रही है। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि देश में माननीय मोदी जी की सरकार में शाहजहाँपुर को कितना लाभ मिल रहा है। मान्यवर, यह संतोष का विषय है कि सरकार के विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण बिजली सस्ती हुई है, क्योंकि सौर ऊर्जा शुल्क वर्ष 2010-2011 में 10.95 रुपये प्रति यूनिट से घटकर 2023-24 में 2.60 रुपये प्रति यूनिट हुआ है। मैं लद्दाख में 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की विद्युत निकासी तथा ग्रिड एकीकरण के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से देश के अन्य भागों में विद्युत ट्रांसमिशन के अनुमोदन के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा देश की ऑफशोर विंड संभाव्यता का सदुपयोग करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए ऑफशोर विंड ऊर्जा परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना का अनुमोदन एक अच्छा कदम है। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में भारत सरकार को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इस सकारात्मक बदलाव के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आज लगभग 60 गीगावाट प्रति वर्ष की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के साथ भारत सोलर मॉड्यूलों की अपनी वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, यह उन सबका ही परिणाम है कि आज लगभग 60 गीगावाट प्रति वर्ष की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के साथ भारत सोलर मॉड्यूलों की अपनी वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करें, तब देश में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता मात्र 2.3 गीगावाट प्रति वर्ष थी, लेकिन जब से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी

के नेतृत्व में सरकार बनी है, वर्ष 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार के प्रयासों का ही यह फल है कि पिछले 10 वर्षों में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता में लगभग 26 गुना वृद्धि हुई है। उच्च दक्षता के सोलर मॉड्यूलों के लिए जो उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई स्कीम) भारत सरकार चला रही है, उससे इस क्षमता में और वृद्धि आएगी एवं देश में न सिर्फ मॉड्यूलों, बल्कि सोलर सेलों एवं उनके उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वेफर, पॉलीसिलिकॉन आदि की उत्पादन क्षमता का भी विकास होगा।

वर्ष 2021 में शुरू की गई सोलर पीएलआई योजना भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जो कि भारत को सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन में न केवल मजबूत बनाएगी, बल्कि अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करेगी और भारत को वैश्विक बाजार में सोलर मॉड्यूलों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगी। सोलर पीएलआई योजना के कारण देश में न सिर्फ सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री जैसे सोलर ग्लास, एल्यूमिनियम फ्रेम, बैकशीट इत्यादि के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। सोलर पीएलआई योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस योजना के तहत तमिलनाडु में थिन फिल्म कैडमियम टेल्युराइड तकनीक पर आधारित भारत की प्रथम सोलर मॉड्यूल उत्पादन फैक्टरी लगाई है। साथ ही इस योजना के तहत सौर सेलों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले इंगोट और वेफर की भारत में प्रथम फैक्टरी लगाई गई है। इस योजना से देश में निवेश एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। सोलर पीएलआई योजना के तहत मंजूर की गई सभी उत्पादन क्षमताओं के चालू हो जाने तक देश में इस योजना से एक लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का अनुमान है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (पीएम-कुसुम) योजना ने सिंचाई के सौरीकरण को बढ़ावा देकर भारतीय कृषि क्षेत्र को परिवर्तित किया है। यह योजना तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है - मौजूदा डीजल पम्पों के स्थान पर सौर पम्पों की स्थापना, व्यक्तिगत कृषि पम्पों के साथ कृषि फीडरों का सौरीकरण करना। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे। उसके लिए किसानों को, जो सौर ऊर्जा का लाभ है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब धान की सिंचाई का समय होता है, बिजली रात को आती है और रात में खेत पर जाने से यह डर लगा रहता है कि कहीं सर्प न मिल जाए।

...(समय की घंटी)... महोदय, आप मुझे बस एक मिनट दे दीजिए।

मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। मैं शाहजहाँपुर से आता हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश में वहाँ पर धान की, गन्ने की कई ऐसी फसलें होती हैं, जिनको पानी की बहुत जरूरत होती है। जब धान की रोपाई होती है, तो 24-24 घंटे तक खेत को पानी में रखना पड़ता है, लेकिन बिजली बार-बार चली जाती है और डीजल बहुत महंगा मिलता है। सौर ऊर्जा के द्वारा इस योजना को कारगर बनाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ होते हुए 2017 से अब तक 69,665 से अधिक

किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 53,250 और किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लागत के अनुपात में अपने अनुदान को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कुसुम योजना से लाभ मिल सके।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम पर और अधिक जोर दें और माननीय प्रधान मंत्री जी के सपनों को साकार करें। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश में पर्यावरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इससे किसान हृष्ट-पुष्ट होंगे; उनके बच्चे, नौजवान बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा।

महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. This particular Ministry is one of the most important Ministries as far as we are concerned for the present and for the future.

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI) *in the Chair.*]

Madam, I come from Cochin. Whenever you land in Cochin airport, once you see outside through the windows of the aeroplane, there will be something inscribed on the boundary walls of the Cochin Airport, 'Sun powers this airport.' That is the only airport in the country which is fully powered by solar energy. This has to be emulated in other parts of the country because both environmentally as well as on the economical aspect, this is one of the best models which we can provide for the country. Now, Madam, as we all know, solar energy is going to be pivotal to our country. We are a blessed country in that way wherein we get enough and more sunshine so that the solar energy can be harnessed. But, whether the Government is doing enough to harness the solar energy is one thing which we will have to examine. Now, my State Kerala boasts of a good solar energy State but it all depends upon the policy and the help provided by the Union Government. As far as the PM *Surya Ghar Muft Bijlee Yojana* is concerned, the hon.

Finance Minister announced a rooftop solarisation programme that will help one crore households which will obtain up to 300 free units of electricity every month. This Scheme needs to be more widened so as to reach more people who cannot afford the huge expenditure on power consumption.

Madam, for an ordinary household, when a solar plant of, at least, 3 kw. is to be installed, the cost comes to around Rs. 3 lakhs and the subsidy given on this account is very minimal. This needs to be increased to, at least, 50 per cent so that more and more people are motivated to switch over to this alternate form of energy.

Madam, why do we need this? What is the need for this renewable energy which is very great today? It is primarily because of the environmental concerns. Climate change is directly related to non-renewable energy. Now, fossil fuels, as we know, are harmful and contribute to global warming. Renewable energy, as we all know, is pollution-free and zero carbon emission. Therefore, non-renewable energy sources, which are very dangerous, have to be excluded, at least, step-by-step. India has a huge potential with long coastline and we can even install windmills in the sea as some developed countries have done. I have a strong reservation as far as hydropower projects are concerned. Even small hydropower projects come under this Ministry. Kerala is a State which has got 54 hydro-electric projects. Madam, you know that all these hydro-electric projects come with a dam. Because of the change in the course of rain and change in the course of rivers, we have seen the natural disasters which are happening in various parts of the country. Cloudbursts and change in the course of rivers are all happening in this country. We have seen the recent disaster in Wayanad and one of the reasons for that was the cloudburst. Kerala has got 54 hydro-electric projects. Many of the dams are very old. There is a dam called Mullaperiyar dam which was constructed in 18th century. That dam is maintained, operated and owned by the State of Tamil Nadu. The problem is that it is made of limestone, its capacity is to the brink and the people over there are living in fear. There has to be some sort of expert committee, particularly, after the Wayanad disaster, to look into the issue as to whether the dams are safe, whether the carrying capacity of the Mullaperiyar dam is safe and to tell the people that they are safe or you have to accept the recommendation of the Kerala Government that we will actually construct a new dam for the State of Tamil Nadu. There are certain statistics which I want to place before you. As far as this Ministry is concerned, against a target of residential sector capacity of 40 gigawatt under the Rooftop Solar Programme Phase-II, only 2,651 megawatt has been installed as of 30th November, 2023.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: Only thirty seconds more, Madam. Of the approximately 4,000 solar mini-grids installed in India, 3,300 are Government financed and only five per cent of these are operational as of July, 2023. India targeted installing 175 gigawatt of renewable energy, while country has achieved only 120 gw.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य, please conclude कीजिए।

SHRI HARIS BEERAN: Madam, I am concluding. You know, as our forefathers say, India lives in villages and I would say that *Atmanirbhar Bharat* will be possible only when the development takes place in villages. Thank you, Madam.

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का मौका दिया है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश का नेतृत्व सम्भाला, तब से उनका एक लक्ष्य यह रहा है कि वे गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, आम आदमी के जीवन में सुधार लाएं और साथ ही साथ देश का विकास करके, भारत देश को एक विकसित देश के रूप में प्रस्तुत करें। अपनी इसी सोच के कारण, उन्होंने देश को ऊर्जा के मामले में self-sufficient बनाने की दिशा में कई योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारे जो कोयला और तेल पर आधारित बिजली उत्पादन के कारखाने थे, उनके साथ-साथ सौर ऊर्जा, wind power, hydro electric, इन सारी चीजों के लिए भी उन्होंने काफी काम किये और उससे आज हमारा देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम द्वारा 'विकसित भारत' मिशन के अंतर्गत पिछले 10 सालों में जो प्रगति हुई है, वह एक रिकॉर्ड है। हम ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था से आज पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और इस growth story में ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है।

महोदया, मैं विपक्ष के साथियों को सुन रहा था। मैं उनके भ्रम को दूर करने के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा बिजली का उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा renewable energy का producer है। भारत की renewable energy की capacity 195 गीगावॉट है, जिसमें सौर ऊर्जा 85.47 गीगावॉट, wind power 46.65 गीगावॉट और hydro power 46.92 गीगावॉट contribute करती है। भारत की non-fossil fuel पिछले 10 सालों में 396 परसेंट बढ़ी है तथा यह 203.99 गीगावाट है, जो भारत की पूरी कैपेसिटी का 45.5 परसेंट है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने 748 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है तथा हम इसमें पिछले 10 साल में 30 गुना बढ़े हैं। विंड पावर में भी हम विश्व में चौथे नंबर पर हैं और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 46.65 गीगावाट है।

हाइड्रो पावर में हम विश्व में पांचवें नंबर पर हैं और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 46.92 गीगावाट है। हमने COP-26 में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है और इसको हम 2030 तक पूरा करने का सोच रहे हैं। हम 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन भी पैदा करने का लक्ष्य बना चुके हैं। इन सबसे 2010-11 के मुकाबले में 2023-24 में हमारा टैरिफ 76 परसेंट कम हुआ है। भारत में प्रधान मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए हंड्रेड परसेंट एफडी खोल दिया है, जिससे फॉरेन के इन्वेस्टर्स यहां आकर पूरा 100 परसेंट तक लगाकर यहां पर कारखाने खोल सकते हैं और इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमने 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा के लिए 75,201 करोड़ रुपए खर्च करके 'पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना' शुरू की गई है, जिससे गरीब आदमी को पीएम आवास भी दिया जाएगा और साथ-ही-साथ उसको मुफ्त बिजली भी मिल जाएगी तथा इससे एक परिवार को लगभग 15,000 से 18,000 रुपए की बचत भी होगी। सूर्य ऊर्जा के लिए 75,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पीएम द्वारा किए गए इन कार्यों से लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का रास्ता भी खुल रहा है। हम 2030 तक 50 परसेंट ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरे कर लेंगे। 2013-14 के बजट में इस क्षेत्र के लिए 1,533.55 करोड़ रुपए आवंटित था, जबकि 2024-25 के बजट में इसके लिए 19,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह पिछले एलोकेशन से डबल है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पर्यावरण को decarbonized करने के लिए नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भी रखा है।

मैं यूपी से आता हूँ। मेरे राज्य में डबल इंजन की सरकार है और इस कारण यूपी पहले पांच रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है और इस वक्त यूपी में हम लोग 28 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहे हैं। यूपी में हमारी सरकार बायो पावर और सोलर पावर पर ज्यादा फोकस कर रही है। 2017 में वहाँ जो सोलर एनर्जी 27 मेगावाट थी, वह 2024 में 2,152 मेगावाट हो गई है। हमने 2025 तक पूरे देश की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का 20 परसेंट हिस्सा बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि सोलर सिटी प्रोग्राम के तहत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने का हम लोगों का लक्ष्य है और इसी तरह हम लोगों ने यूपी के 16 नगर निगमों को भी इस लक्ष्य में शामिल किया है।

2.00 P.M.

आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासन में बिजली की कितनी त्राहि-त्राहि हुआ करती थी। हमारे यूपी के कानपुर, इलाहाबाद, बरेली या कहीं पर भी आप देखिए तो वहां बिजली आती ही नहीं थी, पूरा जनरेटर से चलता था। आज देश के अंदर हम लोग शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और गांवों में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसानों के लिए और एक आम आदमी के लिए इसका कितना सुख है, यह वे ही लोग बता सकते हैं। आज हम किसानों को सोलर पंप्स भी दे रहे हैं, जिससे उनका खर्चा कम हो रहा है और उनको सिंचाई का एक साधन आराम से मिल रहा है।

मैडम, आपको याद होगा कि 2012 में एक ग्रिड फेलियर हुआ था, जिसमें 62 करोड़ लोग 24 घंटे अंधेरे में रहे थे और उसका प्रभाव 21 राज्यों में भी पड़ा था। उस वक्त 24,000 मेगावाट कैपेसिटी के पर्याप्त फ्यूल होने के बावजूद हम लोग ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहे थे। लोग कहते हैं कि आज हमारे बहुत सारे डिस्कॉम्स क्यों नुकसान में चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई सरकारों ने इसको वोट पाने का एक टूल बना लिया है और मुफ्त बिजली बांटकर वे लोगों से वोट ले लेती हैं, जिससे सारे डिस्कॉम्स नुकसान में चल रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सौर ऊर्जा को घरों पर लगाने पर जोर दिया, जिससे एक तरफ जहां डिस्कॉम्स को नुकसान कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं।

आज हमारी सरकार ने सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सौर ऊर्जा की तरफ जाने के लिए कंपल्सरी कर दिया है और सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आज सोलर ऊर्जा के लिए इक्विपमेंट लगाना जरूरी हो गया है। साथ ही साथ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जिन्होंने अपने-अपने सोलर पार्क्स लगा लिए हैं, जिससे वे अपने कारखानों के लिए तो बिजली यूज़ कर ही रही हैं, बाकी बिजली ग्रिड में डालकर उससे पैसे भी कमा रही हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय सेठ: बस, एक मिनट। हमारे विपक्ष के एक साथी ने कहा कि CO₂ का एमिशन कम करना टाइम पास है। यह हम यहां पर सुन रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ: मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ संकल्प है और हम सपनों को साकार करने में भरोसा रखते हैं तथा यह हमने करके भी दिखाया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सस्टेनेबल फ्यूचर का परफेक्ट डेस्टिनेशन बन रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप खत्म करें।

श्री संजय सेठ: भारत में आने वाली नई पीढ़ी के लिए हम एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं। मैं यह सलाह देना चाहता हूँ कि विपक्ष नकारात्मकता फैलाने की बजाय सकारात्मक योगदान दे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य, आपका 10 मिनट्स का समय था, जो समाप्त हो गया। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संजय सेठ: जहां-जहां जिनकी सरकारें हैं, वहां वे इस मिशन को आगे बढ़ाकर देश को ऊर्जा में और सेल्फ सफिशिएंट करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): I thank you, Madam Vice-Chairperson, for this opportunity. In the climate change and in these critical times, we are discussing working of one of the most important Ministries — New and Renewable Energy. And, giving importance to new and renewable energy is the need of the hour. More power generation with less environmental impact and less carbon emission is the need of the hour. This Ministry has a tremendous scope and plays a very important role at this juncture. The entire world, today, is looking after producing renewable energy.

Our hon. Narendra Modiji proved as a successful Prime Minister and is heading the country for the third time. Under his leadership, hon. Finance Minister has given equal importance to renewable energy. In her Budget proposals, hon. Finance Minister has proposed Rs. 19,104 crores for renewable energy sector. If you compare this figure with the UPA Government, the hike is more than 100 per cent.

What is the source of renewable energy? What is the source of power production in our country? Madam, during the last ten years, under the leadership of Shri Narendra Modiji, our Government is functioning. If you compare this with the Congress's UPA Government, power production in our country, between 2014 and 2024, gone up by 79.5 per cent. This is the greatest success of this Government. There are different sources of energy — hydro power, nuclear power, thermal power and renewable energy. Among these, thermal power is not environment-friendly. Between big hydro and small hydropower projects, I would not recommend for big hydropower. It is because most of the big hydropower projects are located in the hilly areas, the Himalayan zone, which has danger for earthquake and hence big dams are not favourable.

Madam, people should know one thing. A country like Germany says 'Goodbye' to nuclear energy. They are not supporting nuclear energy, because the cost of production is also very high. So, the successful way of getting energy is new and renewable energy.

Madam, there is a misconception among the people. People believe that clean energy, green energy and renewable energy are all one and the same. This is not true. Clean energy means clean air.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य, प्लीज़ conclude कीजिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Green energy is no harm to environment; it is pollution-free. When it comes to renewable energy, it depends on solar power. Madam, if you allow me some extra time, I would be grateful. I have already requested the BJP. I also request you for giving me a little more time.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI): Sir, time allotted to you is over.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I have requested and they have given me some extra time. Madam, this is a very important subject. So, I am discussing this issue. I would like say two more things. When we are experiencing the global warming, the only option is renewable energy.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): Please conclude. आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Madam, with your permission, I will take only two more minutes. My suggestion is: North-Eastern States, especially Arunachal Pradesh, known as Sun Rising State, and Ladakh are very important for renewable energy. That is because in Ladakh, out of 365 days in a year, there is sunny weather all these 365 days. So, I request the hon. Minister to look into this aspect and give priority to Ladakh. As regards the solar energy, Ladakh is the best source. Similarly, Arunachal Pradesh is the Sun rising State. So, I would like to request the hon. Minister to give priority to Arunachal Pradesh also for solar energy.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI): Please conclude.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I am concluding, Madam. I come from the North-Eastern Region. I come from Assam. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): प्लीज़, समाप्त कीजिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: For the interest of the North-Eastern Region, I would like to request the hon. Minister to give importance and priority to States like

Assam, to support Assam in making renewable energy, solar energy. This is the best for solar energy. ...(*Interruptions*)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): सर, मैं अगला मेम्बर बुलाने जा रही हूँ। प्लीज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I request the hon. Minister to help the North-Eastern Region. With this, I conclude. Thank you, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): माननीय सदस्य आपका टाइम ओवर हो गया है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): धन्यवाद मैडम। हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं, वह एक बहुत important Ministry है। मैडम, राज्य सभा, Council of States है, और मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में एक new energy model निकला है, जो सत्ता को मजबूत करने का काम करता है। * में एक Ministry of Statistics and Programme's Implementation Report आई थी, Energy Statistics from 2023, जहाँ पर renewable power capacities का अनुमान लगाया गया था। उसमें महाराष्ट्र के लिए कहा गया था और यह राज्य सभा का ही आंसर है, जो रिप्लाई आया है। Wind power, जो महाराष्ट्र में estimate है, वह 98,213 मेगावाट है, पर वहाँ पर generation 5 प्रतिशत हो रहा है। जो small hydropower है, उसकी 786 मेगावाट capacity है, पर generation 48 प्रतिशत हो रहा है। As regards Solar energy, 64,320 मेगावाट की capacity महाराष्ट्र में है, capability है, पर मात्र 7 प्रतिशत हो रहा है। अगर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ यह काम कर रही है, तो क्यों ऐसी accountability उस सरकार से नहीं ले रही है। यहाँ पर PM-KUSUM की बहुत बात की गई, तो मैं महाराष्ट्र पर ध्यान देना चाहूँगी। In Component-A, जो 10 गीगावॉट capacity by installing small solar power plants of 2 MW की capacity decide की थी, जिसमें 700 मेगावाट sanction हो गई है, पर installation शून्य है। यह जुमला है। Sorry, I cannot use the word 'Jumla'; it is unparliamentary. Component-B is about Installing of 20 lakhs standalone off-grid solar water pumps, जिसमें से 2 लाख, 25 हजार sanction किए हैं और सिर्फ 61 हजार install किए गए हैं। 27 प्रतिशत target achieve हुआ है। Component-C is about Solarisation of 15 lakhs existing grid connected agricultural pumps and Feeder Level Solarisation - शून्य पंप individual pump solarisation sanction हुए हैं। ऐसे ही 2 लाख, 75 हजार Agricultural Feeder Solarisation sanction हुआ है, पर शून्य install हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब sanction हो जाते हैं, तो वह पैसा कहां जा रहा है? महाराष्ट्र के खिलाफ यह काम क्यों हो

* Expunged as ordered by the Chair.

रहा है? मैडम, मैं जो भी स्पीच दे रही हूँ, वह सारा राज्य सभा में मंत्रालय की तरफ से जवाब आए हैं। Unstarred Question, Rajya Sabha 2021 में कहा गया था कि तीन सोलर पार्क्स महाराष्ट्र में बन रहे हैं। वे तीनों सोलर पार्क्स या तो complete नहीं हुए हैं या वहां काम की शुरुआत ही नहीं हुई है। यह महाराष्ट्र के साथ * है। मैडम, मेरे एक colleague श्री संदीप कुमार पाठक जी हैं। उन्होंने एक मॉडल के बारे में बताया, जो सिर्फ monopolization हो रहा है, उसके बारे में चेयरमैन सर ने भी कुछ टिप्पणी दी थी। मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि कैसे monopolization होता है और कैसे favourite vendors चुने जाते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, सितंबर, 2023 में एक खास कंपनी है, उसमें कार्यरत Adviser हैं। वह Green Energy Company है, उसके Adviser हैं। अप्रैल 2022 में as a non-institutional member for Centre's Expert Appraisal Committee में उनको जगह दे दी जाती है। Expert Appraisal Committee क्या काम करती है? वह प्रोजेक्ट्स के लिए clearance देती है, that requires Central Government's approval. उसमें छह ऐसे प्रोजेक्ट्स थे और वह जो खास इंडस्ट्री है और जिसके वे एडवाइजर हैं, उस पर चर्चा हो रही थी। उनमें से दो आंध्र प्रदेश की हैं और चार महाराष्ट्र राज्य की हैं। उस मीटिंग में, जिसमें वे एडवाइजर्स शामिल थे, एक्सपर्ट एडवाइजरी कौंसिल के मैम्बर्स थे, उन्होंने महाराष्ट्र के एक उस प्रोजेक्ट को भी अनुमति दी, जो उस कंपनी की सहायता कर रहा था।

मैडम, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि monopolisation में कैसे मदद की जाती है और कैसे favouritism होता है। मैडम, चाइना के बारे में बात की जाती है कि हमें कैसे चाइना से इम्पोर्ट करना discourage करना है। मैडम, ये जो सोलर पॉवर कंपनीज़ है, उसके संबंधित काम से कॉमर्स मिनिस्ट्री जाती है और वे लोग कहते हैं कि हमें चाइना से मदद चाहिए, इसलिए वीजा नॉम्स ईज़ कीजिए। वीजा नॉम्स में उनके लिए तीस इंजीनियर्स आठ फॉरेन पार्टनर्स चाइना के हैं। उनके लिए वीजा नॉम्स ईज़ भी कर दिये जाते हैं। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए वीजा भी ईज़ किया जा रहा है। The Government has allowed Chinese nationals in India for ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): मैडम, आपका समय समाप्त हो गया है।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Last thirty seconds. Government has allowed Chinese nationals in India for Production Linked Incentive Schemes to gain the required knowhow. मैडम, हमें चाइना की जरूरत क्यों है?

मैडम, यहाँ पर सोलर पैनल्स की बात हो रही थी कि कितने सोलर पैनल्स इम्पोर्ट हुए हैं। जो भी सौ प्रतिशत हुआ है, उसमें से 57 प्रतिशत सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ

* Expunged as ordered by the Chair.

टिक टॉक बैन करेंगे, ऐप्स बैन करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जिनमें हमें आत्मनिर्भर होना है, उनमें अभी भी चाइना पर डिपेंडेंट हैं और यह देश के साथ सरासर * है।

महोदया, मैं उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी स्पीच खत्म करूंगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI): Next Member is, Shri Bahubhai Jesangbhai Desai; not present. Then, Shrimati Mahua Maji.

SHRIMATI MAHUA MAJI (Jharkhand): Thank you, hon. Madam, for giving me this opportunity. रिन्यूएबल एनर्जी पर बोलते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में भारत दुनिया का चौथा लार्जैस्ट कंज्यूमर है और इन दिनों ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एनर्जी उत्पादन हेतु विभिन्न विकल्पों को डेवलप करने का जो प्रयास हो रहा है, वह अच्छी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सोलर एनर्जी, हाइड्रो पॉवर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी आदि आती हैं। महोदया, इन सभी एनर्जीज के अलग-अलग फायदे तो हैं, लेकिन ढेर सारे नुकसान भी हैं। मेरा अनुरोध है कि इन्हें ध्यान में रखकर ही इनके उत्पादन की जरूरत है, वरना यह धरती रहने लायक नहीं रहेगी।

महोदया, ग्रीन गैस उत्सर्जन की वजह से वैसे ही ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जो तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। हमें और जनता को पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से वायु प्रदूषण होता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सीसा और आर्सेनिक का उत्सर्जन शामिल है। सोलर पैनल के अपशिष्टों का निपटान भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इससे काफी मात्रा में ई-कचरा बनता है। इन कचरों में मौजूद सीसा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने का प्लान करने के पश्चात ही इनका बहुतायत में उपयोग आरंभ करना चाहिए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्लान बनाया है? ऐसा कहते हैं कि समुद्र के तट पर बड़े-बड़े इलाकों को सोलर पैनल से ढक देने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया और बारिश वगैरह पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

महोदया, एक और रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे हाइड्रो पॉवर एनर्जी कहते हैं। इसके लिए डैम वगैरह का निर्माण करना पड़ता है, जिससे गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं और विस्थापन की विकट समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा भी कहते हैं कि विंड एनर्जी से चिड़िया वगैरह को नुकसान पहुँचता है। जिस तरह से मोबाइल टॉवर से साउथ में नारियल उत्पादन में समस्या आ रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, आँगन से गौरेया जैसे पक्षी गायब हो रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े बढ़ रहे हैं, उससे सीख लेकर हमें प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को गंभीरता से लेकर एनर्जी का उत्पादन करना चाहिए।

* Expunged as ordered by the Chair.

महोदया, मैं केंद्र सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण एनर्जी की तरफ दिलाना चाहूंगी। वह एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भारत में विद्युत का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में देश भर में सात बिजली संयंत्रों में बाईस से अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स सक्रिय हैं। सरकार देश के अन्य हिस्सों में भी परमाणु प्रतिष्ठानों के विस्तार को बढ़ावा दे रही है। चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसे कोयला या गैस संयंत्रों की तुलना में सस्ता माना जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी को स्वच्छ और कार्बन मुक्त एनर्जी का स्रोत भी माना जाता है, मगर सच्चाई यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना के घटित होने पर ये पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र विस्फोट को याद कीजिए कि किस तरह की तबाही थी। गर्मी की वजह से पूरी छत उड़ गई थी। सैकड़ों किलोमीटर की परिधि बंजर हो गई थी और अनिश्चितकाल के लिए वहाँ लोगों का जाने, भोजन सामग्री लाने में रोक लगानी पड़ी थी। जब जापान में सुनामी आई थी, तब समुद्र का पानी 15 फीट ऊँची बाउंड्री वॉल को लांघ कर, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आ गया था, जिससे कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था और वहाँ से रेडिएशन आरंभ हो गया था। वह रेडिएशन प्रशांत महासागर को पार करके, कैलिफोर्निया तक पहुंच गया था। अमेरिका के हाथ-पांव फूल गए थे, तो उसने दुनिया के सबसे बड़े जनरेटर को हवाई जहाज से भेजकर, उसके कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया था। उस समय 50 जापानी साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ठीक करने के लिए उसके अंदर गए थे, तब वे एक तरह से सुसाइड मिशन पर जा रहे थे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखा था, वह हमने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि मैं एक तरह से सुसाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि वह रेडिएशन इतना खतरनाक है कि उन्हें पता भी नहीं कि वहाँ से निकलने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि इस तरह से भारत में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और आगे भी बहुत सारे बनाने का प्लान है। साउथ इंडिया के कोडाइकनाल में न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाने की बात हुई थी, तो वहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक है, जो दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 30 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। चूँकि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका को फॉलो करता है और विकास के पूँजीवादी मॉडल को अपनाता रहा है, इसलिए मैं केंद्र सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि विकास के अंधे दौर में ऊर्जा जरूरतों तो पूरा करने हेतु अंधाधुंध परमाणु ऊर्जा...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सीमा द्विवेदी): कन्क्लूड कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती महुआ माजी: आधा मिनट और बोलने दीजिए।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संबंधी संकट न पैदा करें। परमाणु रिएक्टर संयंत्रों से निकला ईंधन वेस्ट अत्यंत खतरनाक है, इसलिए इसका ध्यान रखकर ही न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, थैंक यू।

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि हमें हरित ऊर्जा की जरूरत है। भारत की जरूरत का 87.7 परसेंट ऑइल हम इम्पोर्ट करते हैं। हमने अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक 232.5 मिलियन टन ऑइल इम्पोर्ट किया और उसके लिए हमने 132.4 बिलियन डॉलर चुकाए। 2022-23 में हमने 157.5 बिलियन डॉलर ऑइल इम्पोर्ट पर चुकाए थे। इस वर्ष हमने जो ऑइल इम्पोर्ट में चुकाए हैं, वे कम हैं, जो सिद्ध करता है कि हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। महोदय, जब हमारे देश में पहले काँग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, तब हमारी फोरन पॉलिसी ऑइल इम्पोर्ट के कारण प्रभावित होती थी। डर लगता था कि हम किसी पड़ोसी देश पर कड़ी कार्रवाई इसलिए न करें, क्योंकि हमें कई ऑइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑइल नहीं देंगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त है। रशिया पर बैन लगाया गया, हमने रशिया से ऑइल इम्पोर्ट किया। हमने चिंता नहीं की, क्योंकि आज हम सशक्त हैं। जहाँ तक फोसिल सोर्सेज का सवाल है, तो भारत इसमें काफी प्रगति कर रहा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन (केजी-जी6), मुंबई हाई, मुंबई Offshore, राजस्थान, असम-अराकार बेसिन, गुजरात, इन सबमें ऑइल एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और Shale से ऑइल निकानले का काम भी इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। महोदय, Shale वे चट्टानें होती हैं, जो बहुत डीप हैं। उनमें भी ऑइल और गैस ट्रेप होती हैं, जिन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसका भी प्रयास चल रहा है। भारत का ज्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। पूरा दक्षिण भारत ही ट्रॉपिकल है। मेरे एक मित्र दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। वे चेन्नई के हैं, मैंने उनसे पूछा कि इस समय क्लाइमेट कैसा है। वे बोले कि यहां तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यही मौसम होता है। जहां हमारे ट्रॉपिकल और सब-ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, वहां सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी रूफटॉप पर गांव में 300 वॉट की एनर्जी का जो लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग 300 यूनिट बिजली पैदा कर करेंगे और वह हमारे घर की खपत के लिए पर्याप्त होगी।

महोदय, मैं अपने घर का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लखनऊ में मेरा घर है। जब मैंने घर बनाया, तो मुझे 20-22 हजार रुपया महीना बिजली का बिल देना पड़ता था। मैंने उस पर पहले 2 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाया, उससे हमारे घर में बिजली, पंखा, फ्रीज चल जाता है। फिर मैंने 5 किलोवाट का लगाया, जिसे मैं ग्रिड में दे देता हूं। हमारे घर में कोई गीजर नहीं है, जो सबसे ज्यादा बिजली खपत करता है, बल्कि सोलर गीजर है और इस समय अगर आप रात में 12 बजे भी चाहो, तो इतना गर्म पानी रहता है कि ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। आज मेरा बिजली का बिल 400-500 रुपया महीना आता है। यह जो मोदी जी की योजना है कि हर घर 300 यूनिट बिजली पैदा होगी, जो कि उसके घर के लिए पर्याप्त होगी। यह सोलर एनर्जी किसानों के लिए बड़ी लाभदायक होगी, क्योंकि हम सोलर पंप लगाएंगे, जिसकी योजना सरकार ने जारी की है। हमारे प्रदेश में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और उन सोलर पंप से किसान सीधे अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

सोलर एनर्जी में अपार संभावनाएं, जो डिग्रेडेड लैंड है, बैरन लैंड है, जहां पर कोई पैदावार नहीं होती, उस पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं और अब हमारे देश का ऐसा किसान जो कुछ पैदावार नहीं कर पाता था, अब वह बिजली पैदा करेगा, सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करेगा और बेचेगा।

महोदय, मैंने खुद देखा है, हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर है। मैं एक टूर में गया बेतवा लिफ्ट कैनाल है, जो नहर निकली है, उस नहर पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, उससे वहां लिफ्ट कैनाल चलता है, उससे बिजली पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SUO-MOTO STATEMENT BY MINISTER

The Situation in Bangladesh

MR. CHAIRMAN: Statement by Minister, Shri S. Jaishankar.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As hon. Members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many Governments. Concerns about recent violence and instability there have been shared across the political spectrum. Since the Election in January, 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarisation in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counselled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. Despite the Supreme Court judgment on 21st July, there was no let up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation, at this stage, coalesced around a one-point agenda, namely, that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down.

On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and Government installations, intensified even as overall levels of violence